यह स्थगन प्रस्ताव एक गम्भीर मामले के बारे में है, तीन दिन से लगातार गोली चल रही है। हमारे स्थगन प्रस्ताव का प्रयोजन यही है कि हम इस विषय पर चर्चा करें। सरकार सोचे कि क्या वह वहां ऐसी स्थिति आगे भी चलने देगी। यह एक गम्भीर स्थिति है। विधि और व्यवस्था भंग हो जाने पर अब केन्द्र का कर्त्तव्य है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे, जबकि देश के किसी भाग से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तो केन्द्र ने हस्तक्षेप किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वहां सेना ने किसी विशेष क्षेत्र का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : जी हां, कुछ पत्रों में प्रकाशित समाचार है कि सारा क्षेत्र सेना के नियंत्रण में है। इसीलिये हम इस मामले पर चर्चा चाहते हैं। दूसरे, जब स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य एक और बात का उत्तर दें। वहां एक विशेष दल ने एक खाद्य आंदोलन संगठित किया है। यहां माननीय मंत्री बताते रहे हैं कि सरकार इस संबंध में क्या क्या कार्यवाही करती रही है। यदि उसके बाद भी वहां वह दल आंदोलन चलाता रहता है तो क्या वहां की सरकार चुपचाप बैठी रहे?

†**श्री अ० क० गोपालन** : यह आंदोलन अचानक एक दिन में तो आरम्भ नहीं हो गया है। वहां की अकाल विमोचन समिति ने बार बार वहां की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की पर वहां की सरकार ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। यदि सरकार उसकी बात सुन लेती और उस पर ध्यान देती तो यह स्थिति न पैदा होती।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : पश्चिमी बंगाल कांग्रेस समिति के उप-सभापति ने केन्द्रीय सरकार पर दोष लगाया है। उनका कहना है कि केन्द्रीय सरकार हमें ठीक समय पर खाद्य नहीं देती।

†**श्री अ० क० गोपालन** : अभी उस दिन प्रधान मंत्री मुझ से पूछ रहे थे कि "क्या यही संसदीय लोकतंत्र है।" आज यह सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, कल प्रश्न काल के बाद जब आपने उन स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दी, तो उस पक्ष के कुछ माननीय सदस्य मेरे पास आये और उन्होंने बताया कि कलकत्ते में अब खाद्य स्थिति बहुत सुधर गयी है, वहां फसल बहुत अच्छी है और मूल्य बहुत नीचे गिर गये हैं। हो सकता है कि इस मामले में कुछ मतभेद हो कि हालत कितनी सुधर गयी है पर इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मूल्य ३ से ५ या ७ रु० प्रतिमन तक नीचे आ गये हैं। यह उन्होंने नहीं कहा था। यह मैं कह रहा हूं। मूल्य कम हो गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। चाहे उन्होंने यह कहा हो या न कहा हो पर यह सच है कि मूल्य कम हो गये हैं। फसल बहुत अच्छी हुई है और शायद इसी के फलस्वरूप मूल्य कम हो गये हैं।

इसके अतिरिक्त, पहले से भी बंगाल में लगभग ५० प्रतिशत व्यक्तियों को राशन कार्ड मिले हुये थे और उन्हें उन कार्डों पर खाद्यान्न मिलता था। यह व्यवस्था सम्पूर्ण कलकत्ता तथा कुछ ग्रामीण जनता पर भी लागू थी। यह तो पहले की बात थी। अब तो यह क्षेत्र और भी बढ़ा दिया गया है और अब राशन व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दी गयी है। अब यह स्थिति है। मेरे कहने का

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

यह मतलब नहीं है कि बंगाल की खाद्य स्थिति अब बिल्कुल ठीक है। पर मेरा कहना है कि वहां की खाद्य स्थिति सुधर ही नहीं रही है बल्कि भारत के कुछ अन्य भागों से अच्छी है। इसमें मेरे लिये गर्व करने की कोई बात नहीं है।

लेकिन हम यहां पर ही खाद्य स्थिति पर नहीं विचार कर रहे हैं, कल दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद् में खाद्य स्थिति पर विचार होने वाला है, राज्यों के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री इस बैठक में भाग लेने आ रहे हैं। हम इस मामले पर अलग-अलग राज्यों की दृष्टि से नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से विचार करना चाहते हैं।

कलकत्ते के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि कलकत्ते और बंगाल के कुछ भागों पर सेना ने नियंत्रण कर लिया है। वास्तव में, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। कल सेना बुला ली गयी थी। कल दोपहर को मैंने बताया था कि सेना नहीं बुलाई गयी है। कल शाम को ६ बजे हावड़ा के कुछ भागों में स्थिति बहुत खराब होने के कारण वहां सेना बुलाई गयी। मैं आपको बताता हूं कि तीन दिन पहले तक भी बंगाल के मुख्य मंत्री ने जानबूझ कर पुलिस को बन्दूकें आदि नहीं दी थीं क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि पुलिस उनका प्रयोग करे। जब बहुत सी बसों, एम्बुलेंस गाड़ियों तथा दूध की गाड़ियों में आग लगा दी गई.....

†**श्री मोहम्मद इलियास** (हावड़ा) : पुलिस एम्बुलेंस गाड़ियों में बैठकर गोलियां चला रही थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: माननीय सदस्य का कहना है कि चूंकि एम्बुलेंस गाड़ी में पुलिस थी अतः उस गाड़ी में आग लगा दी गयी।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : क्या एम्बुलेंस गाड़ियों को पुलिस गाड़ियों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: एम्बुलेंस गाड़ियां सरकारी गाड़ियां नहीं होतीं। बहुत सी दूध गाड़ियां भी जलाई गयीं। इसके अतिरिक्त अन्य लूट पाट व हानि की गयी। जब स्थिति इतनी खराब हो गई, तब मजबूर होकर वहां के मुख्य मंत्री पुलिस को बन्दूक आदि देने की बात पर सहमत हुये, क्योंकि लूटपाट और क्षति के संबंध में स्थिति खराब ही होती जा रही थी।

कल हावड़ा में सबसे पहले मजदूरों के दो दलों में कुछ झगड़ा हो गया। एक दल, जिसमें बहुत से मजदूर थे, मिलों में काम जारी रखने के पक्ष में था और हड़ताल को पसन्द नहीं करता था और उसने काफी समय तक काम भी किया। और दूसरे दल ने उनके काम करने पर आपत्ति की। दोनों दलों में कुछ झगड़ा हो गया। जब उन मजदूरों ने, जो मिलों में काम कर रहे थे, अपना उस दिन का काम समाप्त कर लिया, तो उसके बाद हावड़ा तथा उसके बाद के क्षेत्र में झगड़ा बहुत बढ़ गया। तब सेना बुलाई गयी असैनिक अधिकारियों की मदद के लिये। सेना सिर्फ हावड़ा में ही गयी।

अब मैं बताता हूं कि वहां सेना ने क्या किया। प्रशासन अपने हाथ में लेने की बात तो बहुत दूर की बात है। सेना ने दो काम किये। उसने गाड़ियों पर चढ़कर हावड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र का गश्त किया, दशनगर क्षेत्र की जूट मिल के चारों ओर घेरा डाल दिया ताकि पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर सके जिनसे लूटपाट तथा हत्या आदि का भय हो। पुलिस ने बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसे झगड़ों में लोग मरते ही हैं। पर कई बार लोगों की हत्यायें ऐसे ढंग से की जाती हैं, जोकि हत्या से भी अधिक घृणित होती है। आज के अखबार में एक खबर है कि एक पुलिस मैन मार डाला गया। ठीक है, एक पुलिस मैन मार डाला गया। पर, कैसे उसको मारा गया? उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया गया और एक तलवार से उसको टुकड़े टुकड़े काट डालने का प्रयत्न किया गया। यह बहुत ही जघन्य कृत्य है, यह नग्न जघन्यता है और कलकत्ता में इस प्रकार की जघन्यता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

†**श्री नागी रेड्डी** : जनता पर गोलियां चलाये जाने के फलस्वरूप ये घटनायें हुईं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : मुझे आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे कि प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करूं। प्रधान मंत्री ने एक मामले का जिक्र किया जिसमें एक पुलिस मैन को गाड़ी से बाहर खींच कर मार डाला गया। मैं स्वीकार करता हूं कि यह बहुत खेदजनक बात है। पर प्रधान मंत्री ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि कलकत्ते और हावड़ा में केवल २ दिनों में २७ व्यक्तियों को मार डाला गया। क्या यह सच नहीं है कि तीन चार लाख की जनसंख्या वाले छोटे से नगर में कुछ ही घंटों में ११ व्यक्तियों को मार डाला गया।

आज कलकत्ते जैसे बड़े नगर में जो कुछ हो रहा है, उसका कारण यही है कि सरकार की खाद्य नीति के बारे में लोगों को बहुत असन्तोष है। वहां के खाद्य मंत्री मांग करने पर भी श्री अजित प्रसाद जैन की भांति अपना पद त्यागने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जब कि कलकत्ते में २ दिनों में २७ व्यक्तियों को गीली से उड़ा दिया गया है, प्रधान मंत्री चुपचाप बैठे हैं। क्या उनका यह रवैया ठीक है ? बम्बई के संबंध में भी जब २०० से अधिक आंदोलन में मारे जा चुके, तब जाकर वह संयुक्त महाराष्ट्र व गुजरात के लिये राजी हुये हैं। प्रधान मंत्री को बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति कहा जाता है और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। पर यदि वह ऐसा रवैया अख्तियार करेंगे जैसा कि उन्होंने इस मामले में किया है, तो वह उस इज्जत को गंवा बैठेंगे, जो देश की जनता उनकी करती है।

मेरा निवेदन है कि कलकत्ते की जनता कष्ट में है, संकट में है, पीड़ित है और यदि हम यहां बैठे रहेंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक पुलिस मैन को निर्दयता से मारा गया है, तो मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में लोकतंत्र की सभी आशाओं को हमें हमेशा हमेशा के लिये विदाई देनी पड़ेगी। प्रधान मंत्री के रवैये को देखकर मेरा सन्तुलन नष्ट हो गया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चूंकि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि वह अपना सन्तुलन खो बैठे हैं, अतः मेरे लिये आवश्यक नहीं है कि मैं कुछ अधिक कहूं। मैं समझता हूं कि बेकार में ही वह अपना सन्तुलन खो बैठे हैं क्योंकि मैं उनकी अधिकांश बातों से सहमत होने के लिये तैयार हूं। कलकत्ते में जो कुछ हुआ है उसकी सभी निन्दा करते हैं और कोई उसे पसन्द नहीं करता चूंकि पुलिस मैन की हत्या की घटना बड़ी जघन्य थी, अतः मैंने उसे सभा के सामने रखा।

आंदोलन के कारण ही कलकत्ते में यह स्थिति पैदा हुई है। मैं इस बात को मानने को तैयार हूं। पर यह मामला चर्चा करने लायक नहीं है। माननीय सदस्य का यह कथन सही हो सकता है कि खाद्य के मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार का रवैया अच्छा नहीं है या उसका रवैया बुरा है। और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस विषय पर चर्चा की जा सकती है यदि आप चाहें तो। पर हमें उस मामले को अलग रखना चाहिये।

बात यों है कि एक आंदोलन शरू किया गया था। यदि उस आंदोलन का कारण 'खाद्य' था, तो अब वह कारण नहीं रह गया है। स्थायी रूप से नहीं पर फिलहाल तो वह कारण अब विद्यमान नहीं है क्योंकि अब खाद्य स्थिति बहुत सुधर गयी है।

पुलिस तथा जनता के बीच कई संघर्ष व झगड़े हुये, यह सब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम उनकी निन्दा करते हैं। पर मैं नहीं समझता कि ऐसी परिस्थितियों में आप सरकार से क्या कदम उठाने की आशा करते हैं जबकि चारों तरफ लूटमार हो रही हो।

मैं मानता हूं कि साम्यवादी दल तथा अन्य दलों के बहुत से नेता जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था इस समय जेल में हैं पर विरोधी दल में अभी बहुत से माननीय सदस्य हैं, जो आंदोलन को समाप्त कर सकते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : हम आंदोलन को कैसे समाप्त कर सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आप क्यों नहीं कहते "आंदोलन समाप्त करो"।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : आंदोलन को समाप्त करने की मांग करने में जो लोग समर्थ हैं, वे तो जेलों में हैं। हम आंदोलन को बन्द करने की मांग कैसे कर सकते हैं। हम तो उस समिति के सदस्य भी नहीं हैं। कल मैंने प्रधान मंत्री से निवेदन किया था कि वहां की हालत अच्छी नहीं है। वह हस्तक्षेप करें। मैंने उनसे निवेदन किया कि जनता को दबाने व सताने से कोई लाभ नहीं होगा। केरल के मामले में वह स्वयं केरल गये थे। उन्होंने श्री नम्बूद्रीपाद से कहा कि वह आंदोलन करने वालों से बातचीत करके समझौता करें। क्या इस मामले में वह ऐसा नहीं कर सकते ?

†**श्री मोहम्मद इलियास** : मैं प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का खंडन करता हूं। पश्चिमी बंगाल सरकार की बातें विश्वसनीय नहीं हैं। मुझे हावड़ा से टेलीफोन पर सन्देश मिला है कि वहां सामान्य हड़ताल के समय में बिल्कुल शांति थी। २३ तारीख को लाठी चार्ज हुआ उसके बाद भी शांति ही रही। पर सेना ने आकर गोली चलाई।

बंगाल में सिर्फ एक व्यक्ति, वहां के खाद्य मंत्री की इज्जत बचाने के लिये इतने व्यक्तियों की हत्या की जा रही है। जनता एक मुट्ठी चावल की ही तो मांग कर रही है पर सरकार वह भी नहीं दे सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कलकत्ते में जो कुछ हुआ है,वह बहुत दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा कि यह आंदोलन खाद्य संकट के कारण आरम्भ हुआ है। वहां खाद्यान्नों की कमी, उनके मूल्य तथा वितरण की समस्यायें थीं। खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिये वहां जल्दी से जल्दी खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है। मूल्यों में कुछ कमी हो गयी है और आगे और कमी होने की संभावना भी है। वितरण की व्यवस्था भी सरकार के कथनानुसार सन्तोषजनक ही है। एक शिकायत है कि वहां जो चावल दिया जा रहा है वह अच्छी किस्म का नहीं है। पर बंगाल सरकार क्या करे। बंगाल में इतना अधिक चावल पैदा नहीं होता। अतः बाहर का चावल देने के सिवाय और क्या रास्ता है। हम सभी लोग स्थिति के संबंध में सतर्क व सावधान हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में